दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि:01.06.2023

<u>सि.वा. (मू. प.) 1281/2015</u>

मंजू वत्स एवं अन्य ..... वादीगण

द्वारा: श्री अंकित जैन और श्री आदित्य चौहान, अधिवक्तागण।

बनाम

मीना पांडे ..... प्रतिवादी

द्वारा: श्री गौरव सरीन, श्री एस.के.राउत, श्री अमन मेहरोत्रा एवं श्री हरीश, अधिवक्तागण।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री नवीन चावला

<u>न्या. नवीन चावला (मौखिक)</u>

1. इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16.01.2018 द्वारा, ***विनोद पोपली बनाम रागिनी पोपली और अन्य***, 2015 एससीसी ऑनलाइन डेल 8506 में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देते हुए, वर्तमान वाद की धारणीयता पर एक

संदेह पर विचार किया। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को इस पर प्रस्तुतियाँ देने के लिए बुलाया गया था।

2. दिनांक 11.10.2019 के एक आदेश द्वारा, पक्षकारगण की सुनवाई पर, एक विस्तृत आदेश पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि कम से कम प्रतिवादी की मां स्वर्गीय श्रीमती सीता देवी और वादीगण की मां स्वर्गीय श्रीमती सावित्री देवी द्वारा निष्पादित संयुक्त वसीयत (वसीयतों) के वादीगण के तर्क पर, उसी तारीख को, यानी 16.04.1981 को, उक्त वसीयत प्रथम दृष्टया समदोष के सिद्धांत से प्रभावित नहीं होगी।

3. हालांकि, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि संशोधित वादपत्र की प्रार्थनाओं (सीसीसी) और (सीसीसीसी) को परिसीमा से वर्जित किया जाएगा और समदोष के सिद्धांत के अनुसार खारिज कर दिया जाएगा और इसलिए, प्रार्थना की गई कि इन प्रार्थनाओं को विलोपन कर दिया जाए। इसलिए, न्यायालय ने दिनांक 11.10.2019 के आदेश में निम्नानुसार टिप्पणी की: -

> *"8. वादीगण द्वारा स्वयं श्रीमती सीता देवी के उत्तराधिकारी के रूप में वादांतर्गत संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में वादपत्र में विवाद के मद्देनजर, जो प्रथम दृष्टया समदोष के सिद्धांत से प्रभावित नहीं है, सवाल यह है कि क्या वादपत्र को सीमा पर खारिज किया जा सकता है। यह स्थापित है कि एक वादपत्र को आंशिक रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है जैसा कि इस न्यायालय ने व्हेल*

स्टेशनरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम कोरेस सी.ई. जीएमबीएच और अन्य, (2013) 205 डीएलटी 99 और सत्य पाल गुप्ता बनाम सुधीर कुमार गुप्ता (2016) 230 डीएलटी 73 में अभिनिर्धारित किया था। सेजल ग्लास लिमिटेड बनाम नवेलन मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (2018) 11 एससीसी 780 में उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय में इस स्थिति को दोहराया गया है।

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि इस स्तर पर वादपत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है।

10. श्री सरीन प्रस्तुत करते हैं कि संशोधित वादपत्र की प्रार्थना (सीसीसी) और (सीसीसीसी) में वादीगण द्वारा दावा की गई राहत स्पष्ट रूप से परिसीमा और समदोष के सिद्धांत द्वारा वर्जित है, और न्यायालय उन राहतों के विलोपन का निर्देश दे सकता है। श्री जैन सुनवाई की अगली तारीख पर इस पहलू पर दलीलें देंगे।"

4. मैंने प्रतिवादी द्वारा उठाए गए और यहां ऊपर अभिलिखित किए गए दो मुद्दों पर पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है।

5. प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों का संदर्भ देने से पहले, संशोधित वादपत्र में दिए गए कथनों पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा।

6. वादीगण का यह मामला है कि एफ-45, बाली नगर, नई दिल्ली-110015 नंबर वाली संपत्ति (इसके बाद 'वादांतर्गत संपत्ति' के रूप में संदर्भित) वादीगण की मां श्रीमती सावित्री देवी और प्रतिवादी की मां स्वर्गीय श्रीमती सीता देवी द्वारा

संयुक्त रूप से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 11.07.1960 के माध्यम से खरीदी गई थी। वादीगण आगे यह भी प्रस्तुत करते हैं कि संपत्ति की खरीद के बाद, निर्माण के प्रयोजनों के लिए, ऋण के रूप में एक निश्चित राशि उत्पन्न करना आवश्यक था। वादीगण का दावा है कि 1966 के दौरान सहायक आवास आयुक्त (ऋण), नई दिल्ली के माध्यम से दिल्ली प्रशासन द्वारा ऋण प्रदान किया जाता था। हालाँकि, इस तरह का ऋण केवल संपत्ति के एकमात्र मालिक को दिया जाता था।

7. वादीगण का दावा है कि प्रतिवादी के पिता- स्वर्गीय श्री जगदीश सरूप वत्स उक्त प्राधिकारी से ऋण प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार थे, और उनके अनुरोध पर, वादीगण की मां- स्वर्गीय श्रीमती सावित्री देवी ने प्रतिवादी की मां- स्वर्गीय श्रीमती सीता देवी के पक्ष में दिनांक 18.03.1966 को एक विक्रय विलेख निष्पादित किया, ताकि ऋण जुटाने के प्रयोजनों के लिए उसे संपत्ति के एकमात्र मालिक के रूप में दिखाया जा सके। वादीगण का दावा है कि हालांकि, यह सहमति हुई थी कि वादीगण की मां अन्यथा वादांतर्गत संपत्ति की सह-मालिक बनी रहेगी।

8. वादीगण का यह भी दावा है कि उसके बाद ऋण की पूरी राशि परिवार के धन से चुका दी गई थी।

9. वादीगण का दावा है कि परिवार की उपरोक्त समझ संयुक्त वसीयत जो कि दोनों पक्षों की माताओं द्वारा दिनांक 16.04.1981 को निष्पादित की गई थी और जिसके आधार पर वर्तमान वाद दायर किया गया है, में भी प्रतिबिंबित हुई थी।

10. वादीगण का दावा है कि यह केवल 2014 की ही बात है, जब वादीगण ने प्रतिवादी से वादांतर्गत संपत्ति का बंटवारा करने का अनुरोध किया, तब प्रतिवादी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिससे वादीगण को वर्तमान वाद दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

11. मूल रूप से, वादीगण द्वारा केवल विभाजन विलेख के लिए प्रार्थना करते हुए वाद दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि पक्षकारगण की माताएं वादांतर्गत संपत्ति की सह-मालिक थीं और उन दोनों द्वारा निष्पादित संयुक्त वसीयत(तों) के संदर्भ में, वादीगण वादांतर्गत संपत्ति में हिस्से के हकदार थे और इसलिए, वादांतर्गत संपत्ति के विभाजन विलेख के हकदार थे।

12. प्रतिवादी ने लिखित बयान दायर किया जिसमें कहा गया कि 18.03.1966 को विक्रय विलेख के निष्पादन के साथ, वादीगण की मां के पास वादांतर्गत संपत्ति में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं बचा था। प्रतिवादी ने आगे दलील दी कि स्वर्गीय श्रीमती सीता देवी ने प्रतिवादी के पक्ष में वादांतर्गत संपत्ति की वसीयत करने के लिए दिनांक 08.04.1988 की एक वसीयत छोड़ी थी।

प्रतिवादी ने वाद में वादीगण द्वारा प्रतिपादित दिनांक 16.04.1981 की वसीयत की वास्तविकता को भी नकार दिया।

13. प्रतिवादी की दलीलों के आधार पर, वादीगण ने वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति के लिए आवेदन किया, ताकि प्रार्थना (सीसीसी) और (सीसीसीसी) सहित अतिरिक्त प्रार्थनाएं शामिल की जा सकें, जिन्हें यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> "(सी. सी. सी.) घोषणा की डिक्री पारित करें कि दिनांक 18.03.1966 का विक्रय विलेख एक दिखावटी दस्तावेज था और श्रीमती सीता देवी को नगर निगम संख्या एफ-45, बाली नगर, नई दिल्ली की लगभग 200 वर्ग गज की अचल संपत्ति के किसी भी हिस्से पर कोई स्वामित्व अधिकार प्रदान नहीं किया;
>
> (सी. सी. सी. सी.) रद्दकरण की डिक्री पारित करें, जिसके द्वारा दिनांक 18/03/1966 का विक्रय विलेख रद्द किया जा सके, जो कि श्रीमती सीता देवी के पक्ष में पंजीकरण संख्या 6169 पुस्तक सं. I, जिल्द सं. 1569 पृष्ठ सं. 163 से 164 में दिनांक 23.03.1966 को उप-रजिस्ट्रार, कश्मीरी गेट, दिल्ली में पंजीकृत किया गया था एवं श्रीमती सावित्री देवी द्वारा निष्पादित किया गया था।

14. वादपत्र में संशोधन की अनुमति वादीगण के पक्ष में दिनांक 15.12.2016 के आदेश के तहत दी गई थी, जिसमें प्रतिवादी के सभी आक्षेपों को वर्तमान वाद के विचारण में विचार करने के लिए तैयार रखा गया था।

15. मामले की उपरोक्त पृष्ठभूमि में, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वादीगण की स्वयं की दलील है कि वादीगण की मां स्वर्गीय श्रीमती सावित्री देवी ने अधिकारियों को धोखा देने और ऋण प्राप्त करने के लिए दिनांक 18.03.1966 को विक्रय विलेख निष्पादित किया था। ***विनोद पोपली*** *(पूर्वोक्त)* में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, वह प्रस्तुत करता है कि, इसलिए, वादीगण का दावा समदोष के सिद्धांत पर खारिज कर दिया जा सकता है और संपत्ति प्रतिवादी की मां स्वर्गीय श्रीमती सीता देवी के विशेष स्वामित्व में रहेगी।

16. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि वादीगण को हमेशा 18.03.1966 के विक्रय विलेख के बारे में पता था जिसे उनकी मां ने प्रतिवादी की मां के पक्ष में निष्पादित किया था। वर्तमान वाद केवल 2015 में दायर किया गया था, यानी विक्रय विलेख के निष्पादन के लगभग 50 साल बाद। ***श्रीमती सीमा ठाकुर बनाम भारत संघ और अन्य,*** 2015 एससीसी ऑनलाइन डेल 11386 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, वह प्रस्तुत करता है कि विक्रय विलेख को चुनौती देने वाली राहत को परिसीमा द्वारा वर्जित किया

जाएगा और इसलिए, संशोधित वादपत्र की प्रार्थना (सीसीसी) और (सीसीसीसी) खारिज की जा सकती हैं।

17. वहीं दूसरी ओर, वादीगण के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'सीपीसी') के आदेश XII नियम 6 के सिद्धांतों को वादपत्र में की गई एक विशेष प्रार्थना को खारिज करने के लिए लागू किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान मामले में इस तरह के समाधान को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। **करण कपूर बनाम माधुरी कुमार,** (2022) 10 एससीसी 496; **हिमानी अलॉयज लिमिटेड बनाम टाटा स्टील लिमिटेड,** (2011) 15 एससीसी 273; **एस.एम. आसिफ बनाम वीरेंद्र कुमार बजाज,** (2015) 9 एससीसी 287; **एक्सप्रेस टावर्स बनाम मोहन सिंह और अन्य,** 2006 एससीसी ऑनलाइन डेल 929; और **मनीषा कमर्शियल लिमिटेड बनाम एनआर डोंगरे और अन्य**, 2000 (52) डीआरजे, के निर्णयों पर भरोसा करते हुए वह प्रस्तुत करता है कि सि.प्र.सं. के आदेश XII नियम 6 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एक डिक्री पारित करने के लिए, जो एक विवेकाधीन शक्ति है, प्रस्तुति विशिष्ट, स्पष्ट और श्रेणीबद्ध होनी चाहिए। भले ही दावा की गई प्रस्तुति कानून के प्रश्न पर हो, यदि यह जटिल प्रकृति की है, तो न्यायालय आम तौर पर उक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए डिक्री पारित करने से इनकार कर देगा। वह प्रस्तुत करता है

कि वर्तमान मामले में, वादीगण की कोई प्रस्तुति नहीं है, जिसके आधार पर इस स्तर पर विचाराधीन प्रार्थनाओं को खारिज किया जा सकता है।

18. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता की इस प्रस्तुति पर कि संशोधित वादपत्र की प्रार्थना (सीसीसी) और (सीसीसीसी), समदोष के सिद्धांत से प्रभावित होंगी, वादीगण का विद्वान अधिवक्ता **केदार नाथ मोटानी और अन्य बनाम प्रहलाद राय और अन्य,** एआईआर 1960 एससी 213; **डाल चंद बनाम बाबू राम एवं अन्य,** एआईआर 1981 एएलएल 335; **सीता राम बनाम राधाबाई एवं अन्य,** एआईआर 1968 एससी 534; **टी.पी. पेदरपर्मल चेट्टी बनाम आर. मुनियांडी सर्वई और अन्य,** 1908 एससीसी ऑनलाइन पीसी 5; और **बबिता पाल एवं अन्य बनाम जे.जगदीश बंसल**, 2013 (133) डीआरजे 332 (डीबी), पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत करता है कि यह वादीगण का मामला नहीं है कि कथित विक्रय विलेख वादीगण की मां द्वारा किसी तीसरे पक्ष के साथ धोखाधड़ी को बरकरार रखने के लिए निष्पादित किया गया था। वादीगण का मामला यह है कि पक्षकारगण को वादांतर्गत भूमि पर निर्माण के प्रयोजनों के लिए एक ऋण की आवश्यकता थी, और जैसा कि यह एक शर्त थी कि ऐसा ऋण केवल संपत्ति के एकमात्र मालिक को दिया जाएगा, विक्रय लेनदेन इस स्पष्ट समझ के साथ किया गया था कि हालांकि, इसका विशेष स्वामित्व केवल प्रतिवादी की मां पर नहीं होगा या किसी भी तरह से वादीगण की मां को ऐसे स्वामित्व अधिकारों से वंचित

नहीं किया जाएगा। वास्तव में, ऋण पूरी तरह से परिवार के धन से चुकाया गया है और इसलिए, अन्यथा भी, किसी तीसरे पक्ष के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। वह प्रस्तुत करता है कि, इसलिए, समदोष का सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

19. दावे को परिसीमा द्वारा वर्जित किए जाने के प्रश्न पर, वादीगण का विद्वान अधिवक्ता, **गैनन डंकर्ले एंड कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ**, (1969) 3 एससीसी 607; **श्री बिस्वनाथ बनिक एवं अन्य बनाम सुलंगा बोस एवं अन्य**, (2022) 7 एससीसी 731; **मुसम्मत बोलो बनाम मुसम्मत कोकलान और अन्य,** कलकत्ता साप्ताहिक टिप्पणी खंड XXXIV पृ. 1169; और **पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम गुरदेव सिंह,** (1991) 4 एससीसी 1 पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत करता है कि वाद दायर करने और उपरोक्त प्रार्थना करने के लिए वाद-हेतुक केवल तभी उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने, 18.03.1966 के विक्रय विलेख के आधार पर, अपनी मां के पक्ष में वादांतर्गत संपत्ति के विशेष स्वामित्व अधिकारों का दावा किया। ऐसी तारीख से पहले, जैसा कि प्रतिवादी की मां ने स्वीकार किया था कि विक्रय विलेख पर कार्रवाई नहीं की जानी थी, वादीगण की मां या वादीगण के लिए मुकदमा दायर करने के लिए कोई वाद-हेतुक नहीं था। वह प्रस्तुत करता है कि, इसलिए, वर्तमान वाद परिसीमा की अवधि के भीतर है। वह प्रस्तुत करता है

कि ***सीमा ठाकुर (पूर्वोक्त)*** का निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि, उक्त मामले में, वादीगण ने पिछली न्यायिक कार्यवाही में विक्रय विलेख के निष्पादन को स्वीकार किया था और उसके बाद इसकी अवैधता का मामला बनाया गया था।

20. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर में, आरंभ में अपनी प्रस्तुति को दोहराते हुए, आगे कहा कि प्रतिवादी की मां की मृत्यु 28.06.1991 को हुई थी। इसलिए, भले ही वादीगण के मामले पर विश्वास किया जाए, वादीगण का बंटवारा मांगने का अधिकार उस दिन उत्पन्न हुआ होगा। केवल इसलिए कि प्रतिवादी के पिता की मृत्यु 2014 में हुई थी, यह वादीगण को वर्तमान वाद दायर करने के लिए एक नया वाद-हेतुक नहीं दे सकता है।

21. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता की इस प्रस्तुति का वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह दोहराते हुए खंडन किया है कि वाद दायर करने के लिए वाद-हेतुक और विचाराधीन प्रार्थनाएँ केवल तभी उत्पन्न हुईं जब प्रतिवादी ने विक्रय विलेख पर भरोसा करते हुए अपनी मां के पक्ष में वादांतर्गत संपत्ति का एक विशेष स्वामित्व स्थापित किया। इससे पहले, पक्षकारगण के बीच कोई विवाद नहीं था, जिसमें वादांतर्गत संपत्ति के विभाजन की मांग करने के लिए वादीगण का वाद-हेतुक भी शामिल था। वह प्रस्तुत करता है कि, इसलिए, वाद परिसीमा की अवधि के भीतर है।

22. मैंने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

23. जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है, जिन दो मुद्दों का निर्धारण किया जाना है वे हैं:-

क) विचाराधीन प्रार्थनाएं समदोष के सिद्धांत के आधार पर अस्वीकार की जा सकती हैं;

ख) विचाराधीन प्रार्थनाएं परिसीमा द्वारा वर्जित हैं।

24. उपरोक्त दोनों मुद्दों पर मेरा उत्तर नकारात्मक है।

25. शुरुआत में, सि.प्र.सं. के आदेश XII नियम 6 पर लागू सिद्धांतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

26. ***करण कपूर*** *(पूर्वोक्त)* मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सि.प्र.सं. का आदेश XII नियम 6 किसी न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, जिसका प्रयोग केवल वहीं किया जाना चाहिए जहां तथ्यों और दस्तावेजों की विशिष्ट, स्पष्ट और श्रेणीबद्ध प्रस्तुति अभिलेख पर हो, अन्यथा, न्यायालय सि.प्र.सं. के आदेश XII नियम 6 की शक्ति को लागू करने से इनकार कर सकता है।

27. वास्तव में, ***मनीषा कमर्शियल लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी पक्ष के लिए सि.प्र.सं. के आदेश XII नियम

6 को ऐसे मामलों में लागू करना उचित नहीं होगा जहां विधि के कठिन और जटिल प्रश्न या मुद्दे उठे हों।

28. उपरोक्त परीक्षणों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, यह वादीगण का मामला नहीं है कि 18.03.1966 का विक्रय विलेख वादीगण की मां और प्रतिवादी की मां द्वारा वादांतर्गत संपत्ति पर निर्माण के लिए ऋण पाने के लिए दिल्ली प्रशासन को धोखा देने के लिए निष्पादित किया गया था। वास्तव में, वादीगण का दावा है कि उक्त ऋण पूरी तरह से चुका दिया गया था।

29. ***विनोद पोपली*** (पूर्वोक्त) में, यह वादी का अपना मामला था कि उसने प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में एक पंजीकृत उपहार विलेख निष्पादित किया था और भारी नुकसान के कारण अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए प्रतिवादी सं.1 के साथ तलाक का झूठा मामला भी स्थापित किया था। यह उक्त दलीलों के कारण था कि इस न्यायालय ने समदोष के सिद्धांत को लागू किया, और पाया कि वादी न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करने का दोषी था।

30. ***केदार नाथ मोटानी*** *(पूर्वोक्त)* में, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां दोनों पक्षकारगण यह नहीं दिखाते हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति को धोखा देने या कोई गैरकानूनी कार्य करने की कोई साजिश थी, समदोष की सूक्ति लागू नहीं होगी।

31. ***सीता राम*** *(पूर्वोक्त)* में, उच्चतम न्यायालय ने समदोष के सिद्धांत और इसके अनुप्रयोग पर अपवादों की व्याख्या की, जो निम्नानुसार है: -

> "**11**. यह सिद्धांत कि न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के कहने पर, जो स्वयं किसी अवैध कृत्य या धोखाधड़ी में लिप्त है, एक अवैध अनुबंध को लागू करने से इंकार कर देगा, "समान या पारस्परिक दोष" की उक्ति द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। लेकिन जैसा कि एंसन के प्रिंसिपल्स ऑफ द इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, 22वें संस्करण, पृष्ठ 343 में कहा गया है: ऐसे असाधारण मामले हैं जिनमें किसी व्यक्ति को उस अवैध संविदा के परिणामों से छुटकारा मिल जाएगा जिसमें वह शामिल हुआ है - ऐसे मामले जिनमें यह कहावत लागू नहीं होती है। वे तीन वर्गों में विभाजित हैं: जहां अवैध उद्देश्य को अभी तक पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया गया है, इससे पहले कि इसे भुगतान किए गए धन या इसके आगे वितरित किए गए सामान की वसूली करने की मांग की जाए; (ख) जहां वादी प्रतिवादी के समान समदोष में नहीं है; (ग) जहां वादी को अपना दावा करने के लिए अवैधता पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है।

32. आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि जहां पक्षकारगण समदोष में नहीं हैं, वहां कम दोषी पक्ष संविदा के तहत भुगतान किए गए धन या हस्तांतरित संपत्ति को पुनर्प्राप्त कर सकता है, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे ऐसी संपत्ति हस्तांतरित की गई है, वह वादीगण के प्रति प्रत्ययी कर्तव्य के अधीन है।

33. वर्तमान मामले में, वादीगण का मामला यह नहीं है कि विषय विक्रय विलेख किसी अवैध या अनैतिक कार्य को अंजाम देने के लिए निष्पादित किया गया था। जैसा कि टिप्पणी की गई है, यह वादीगण का मामला है कि विक्रय विलेख ऋण प्राप्त करने की शर्त को पूरा करने के लिए निष्पादित किया गया था, जो पक्षकारगण की माताओं के पारस्परिक लाभ के लिए था। ऋण न चुकाने का कोई इरादा नहीं था और, वास्तव में, ऋण पूरी तरह चुकाया गया। वादीगण के मामले के अनुसार, प्रतिवादी की मां, वास्तव में, एक प्रत्ययी की हैसियत से वादीगण के लिए या उनकी ओर से संपत्ति का स्वामित्व रखेगी।

34. उपर्युक्त को देखते हुए, मेरी राय में, समदोष का सिद्धांत, कम से कम, प्रथम दृष्टया मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है, ताकि इस न्यायालय को सि.प्र.सं. के आदेश XII नियम 6 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग में विषयगत प्रार्थनाओं को खारिज करने वाली डिक्री पारित करने का अधिकार दिया जा सके।

35. परिसीमा के मुद्दे पर आते हुए, वादीगण का मामला यह है कि प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान दाखिल करने तक, इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं था कि वादीगण की मां और प्रतिवादी की मां वादांतर्गत संपत्ति की सह-मालिक थीं; वास्तव में वाद उसी आधार पर दायर किया गया था। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दावा किया है कि यह केवल तब होता है जब प्रतिवादी द्वारा

लिखित बयान में दिनांक 18.03.1966 के विक्रय विलेख के आधार पर प्रतिवादी की मां के अनन्य स्वामित्व की दलील दी गई थी, कि उक्त विक्रय विलेख को चुनौती देने के लिए वादीगण के पक्ष में वाद हेतुक उत्पन्न हुआ। उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादी की मां स्वर्गीय श्रीमती सीता देवी की कथित वसीयत दिनांक 16.04.1981 पर भरोसा जताया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिलिखित किया गया है:

"जबकि मैं, उपरोक्त नामजद निष्पादक, मकान सं. एफ -45, बाली नगर, नई दिल्ली का मालिक हूं, जो ढाई मंजिला इमारत है। यह प्लॉट मूल रूप से उपरोक्त नामित निष्पादक और उसकी बहन श्रीमती सावित्री देवी वत्स द्वारा संयुक्त रूप से खरीदा गया था, लेकिन बाद में, आपसी सहमति से इसे सिर्फ निष्पादक के नाम पर अंतरित कर दिया गया ताकि वह इसके निर्माण के लिए ऋण प्राप्त कर सके। भवन का निर्माण निष्पादक और उसकी बहन श्रीमती सावित्री देवी वत्स के संयुक्त धन से किया गया था और यहां तक कि ऋण की राशि की किस्तें भी उनके द्वारा संयुक्त रूप से भुगतान की जा रही हैं, हालांकि इसका भुगतान सिर्फ निष्पादक के नाम से किया जा रहा है।

36. ***गैनन डंकरले*** *(पूर्वोक्त) में,* उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मुकदमा करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि मुकदमे में दावा किए गए

अधिकार और उसके उल्लंघन का एक उपार्जन न हो, या कम से कम प्रतिवादी द्वारा उस अधिकार का उल्लंघन करने के लिए एक स्पष्ट और सुस्पष्ट खतरा हो, जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है।

37. ***बिस्वनाथ बनिक और अन्य*** *(पूर्वोक्त)* में, उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि वादहेतुक केवल उस तारीख को उत्पन्न हुआ कहा जा सकता है जब वादी के अधिकार को चुनौती दी जाती है।

38. किसी भी स्थिति में, परिसीमा तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न है। प्रतिवादी यहां यह दावा कर रहा है कि वादपत्र की अंतर्वस्तु के आधार पर, वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है। मुझे उक्त प्रस्तुतीकरण में कोई गुणागुण नहीं दिखता। जब वादीगण ने यह दावा कर दिया है कि लिखित बयान दाखिल होने तक, प्रतिवादी या उसके पूर्ववर्ती-हितधारक वादांतर्गत संपत्ति पर एक विशेष अधिकार का दावा नहीं कर रहे थे, और इस बात की कोई प्रस्तुति नहीं है कि प्रतिवादी ने किसी भी समय लिखित बयान दाखिल करने से पहले वादांतर्गत संपत्ति के लिए एक विशेष अधिकार स्थापित किया था, परिसीमा के मुद्दे की प्रस्तुति पर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है।

39. ***श्रीमती सीमा ठाकुर*** *(पूर्वोक्त)* मामले में, न्यायालय ने पाया कि वादी ने कम से कम दो पिछली न्यायिक कार्यवाहियों में स्पष्ट रूप से विक्रय विलेख के निष्पादन को स्वीकार किया था। इसमें वादी ने यह दोष पिछली न्यायिक

कार्यवाहियों में उसका प्रतिनिधित्व करने वाले वकील पर मढ़ने की मांग की। न्यायालय ने उपरोक्त प्रस्तुतिकरण के पक्ष में नहीं पाया। इसलिए, न्यायालय ने पाया कि दस्तावेज़ के निष्पादन को स्वीकार करना और उसके आधार पर मुकदमा दायर करना, यह एक ऐसा मामला था जहां डिक्री सि.प्र.सं. के आदेश XII नियम 6 के तहत पारित की जा सकती थी। वर्तमान मामले में तथ्य, उन तथ्यों से पूरी तरह अलग हैं जिनका सामना ***श्रीमती सीमा ठाकुर*** *(पूर्वोक्त)* के मामले में न्यायालय को करना पड़ा था।

40. मुझे प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता की इस प्रस्तुति में भी कोई दम नजर नहीं आता कि वाद दायर करने का वाद-हेतुक प्रतिवादी की मां की मृत्यु से उत्पन्न हुआ। कोई सह-मालिक सह-मालिकों के पूर्ववर्ती-हितधारक की मृत्यु पर संपत्ति का तत्काल विभाजन प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा पक्ष एक साथ रहने का विकल्प चुन सकता है। इसलिए, वाद-हेतुक तब उत्पन्न होगा जब सह-मालिकों में से एक दूसरों से अलग होने के लिए अपनी राय व्यक्त करता है।

41. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मुझे प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता की इस चुनौती में कोई दम नहीं दिखता है कि विषयगत प्रार्थनाओं को परिसीमा द्वारा बाधित किया जा रहा है।

42. यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यहां ऊपर की गई कोई भी और सभी टिप्पणियाँ, जिनमें परिसीमा का प्रश्न भी शामिल है, केवल प्रथम दृष्टया प्रकृति

की हैं और पक्षकारगण द्वारा अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद, गुणागुण के आधार पर वाद के अंतिम न्यायनिर्णयन के समय इस न्यायालय को बाध्य नहीं किया जाएगा।

43. मुद्दे विरचित करने के लिए 24 जुलाई, 2023 को सूचीबद्ध।

न्या. नवीन चावला

1 जून, 2023/आरवी/आरएन/एएन

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*